

अमित शाह



गृह एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

अर्ध. शा. पत्र संख्या आर-11016/18/2022 सीडी

दिनांक 16 जून, 2023

श्री ज्योतिंद्र मेहता जी,

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय लगातार सहकारिता क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए कार्य कर रहा है। मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र के **सभी हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है** और सहकारी समितियों के आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ा रहा है।

देश के **1,514 शहरी सहकारी बैंक** सहकारिता क्षेत्र के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बैंकों को वर्षों से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समितियां परिसंघ मर्यादित (नैफकब) से भी मेरा लगातार संवाद बना हुआ है।

मैंने शहरी सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का मंत्रालय में गहन अध्ययन करवाया और मेरी **माननीया वित्तमंत्री जी तथा गवर्नर RBI के साथ चर्चा हुई**। सचिव स्तर पर भी वित्तीय सेवाएं विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैठकें हुईं।

आपको जानकर खुशी होगी कि **शहरी सहकारी बैंकों के सुदृढीकरण के लिए** RBI ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

- i. **शहरी सहकारी बैंक अपनी नई शाखाएँ** पिछले वित्तीय वर्ष के शाखाओं की संख्या के 10% तक (अधिकतम 5 शाखाएँ) RBI के पूर्वानुमति के बिना तथा RBI के पूर्वानुमोदन, दोनों मार्ग से, खोल सकेंगे।
- ii. RBI ने वाणिज्यिक बैंकों की तरह शहरी सहकारी बैंक सहित सभी सहकारी बैंकों के **निदेशक मण्डल को समझौता निपटान/ One Time Settlement (OTS)** नीति बनाने के लिए अधिकृत कर दिया है।
- iii. शहरी सहकारी बैंकों के साथ संपर्क हेतु **RBI में नोडल अधिकारी** को नामित किया गया है।

- iv. शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दो साल की अतिरिक्त समय सीमा दी गयी है।
- v. शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, CEO, आदि की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/ बर्खास्तगी हेतु RBI द्वारा 90 दिनों की तथा ऑडिटर की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/ बर्खास्तगी हेतु 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।
- vi. शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं (door-step banking services) प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है।
- vii. शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा भी दोगुनी से अधिक कर दी गई है।

अतः, मैं आशा करता हूँ कि इन कदमों से न केवल सभी शहरी सहकारी बैंक सशक्त होंगे बल्कि अपनी कार्यक्षमता और व्यवहार्यता को पारदर्शी तरीके से बढ़ाते हुए सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे।

आपका,

(हस्ता- /)

(अमित शाह)

श्री ज्योतिंद्र मेहता,

अध्यक्ष,

राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं

ऋण समितियां परिसंघ मर्यादित (नैफकब),

दिल्ली.

प्रतिलिपि: अध्यक्ष/चेयरमैन, सभी शहरी सहकारी बैंक

(अमित शाह)



D.O. Letter No. R- 11016/18/2022- CD

Dated: 16 June, 2023

Shri Jyotindra Mehta Ji,

As you are aware, Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi has created a separate Ministry of Cooperation in July 2021 to realize his vision of '**Sahakar se Samridhi**'. The Ministry of Cooperation, through continuous consultation with the sectoral stakeholders, is mandated to identify issues and constraints in the overall development of the cooperatives and to explore feasible and sustainable solutions. The **constant consultations with all stakeholders** have not only helped a planned progress in the field of cooperation but also have resulted in ensuring viable and profitable business development in cooperatives.

The country's **1,514 Urban Cooperative Banks (UCBs)** are playing a significant role in the cooperative development by meeting urban cooperative credit needs. Multiple issues and difficulties faced by these banks were pending for suitable resolution for long. The National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited (NAFCUB) was in constant touch with me requesting quick resolution of such difficulties which restricted their expansion and business performance.

I directed the Ministry officers to conduct an in-depth examination of the issues, challenges and difficulties faced by Urban Co-operative Banks. A series of Meetings were held at the Secretary level with the senior officers of Department of Financial Services and the Reserve Bank of India. I have had several **rounds of discussions with Hon'ble Finance Minister and RBI Governor** to sustainably address such issues and difficulties.

You may be delighted to know that with our relentless efforts and consultations with stakeholders, the following important **steps have been taken by RBI to strengthen the Urban Co-operative Banks:**

- i. **UCBs can now open their new branches** up to 10% (maximum 5 Branches) of the total number of branches without prior approval of RBI in addition to the existing provision on opening branches through approval route.

- ii. **Board of Directors of UCBs** have now been empowered to formulate their own policy **for Compromise Settlements/One Time Settlement (OTS)** like that of Commercial Banks.
- iii. A **Nodal officer has been nominated in RBI** for Urban Co-operative Banks for establishing regular communication with the sector.
- iv. UCBs **have been allowed an additional period of two years** to achieve **Priority Sector Lending (PSL) targets**.
- v. A **time limit of 90 days** has been fixed for appointment/ re-appointment/ dismissal of **Chairman, Managing Director, CEO**, and **30 days fixed** for appointment / re-appointment/dismissal of **Auditors**.
- vi. UCBs have been permitted to provide **door-step banking services** to their customers.
- vii. **Individual housing loan limits** for UCBs have been extended more than two times of the existing permissible limit.

I hope that the above constructive steps will successfully address the issues and difficulties of UCBs and strengthen the operation and governance of UCBs. I am also confident that our efforts will ensure **increased efficiency, transparency and viability in UCBs while** assuring precious contribution towards cooperative development.

Sd/-

(AMIT SHAH)

Shri Jyotindra Mehta,

President,

National Federation of Urban Cooperative Banks and
Credit Societies Limited (NAFCUB),

Delhi.

Copy to: President/Chairman/CEO- All Urban Cooperative Banks.


(AMIT SHAH)